AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

समकालीन दक्षिण एशिया में चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का भू–रणनीतिक प्रभाव; भारत के पारंपरिक प्रभुत्व, सुरक्षा और आर्थिक हितों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां: एक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
चन्द्र प्रकाश पाठक
शोधार्थी
राजनीति विज्ञानं विभाग
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रारम्भ में एक वैश्विक आर्थिक एवं संपर्क परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापारिक तथा अवसंरचनात्मक संपर्क को सुदृढ़ करना था, किंतु समकालीन परिप्रेक्ष्य में इसका स्वरूप मात्र आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहा है। यह पहल अब चीन की व्यापक भू–आर्थिक, भू–राजनीतिक तथा सामरिक रणनीति का प्रमुख उपकरण बन चुकी है, जो उसकी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के साथ मिलकर दक्षिण एशिया के पारंपरिक शक्ति–संतुलन को प्रभावित कर रही है। इस परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव भारत पर पड़ता है, क्योंकि दक्षिण एशिया ऐतिहासिक रूप से उसके राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमुख क्षेत्र रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल तथा भूटान में चीन की बढ़ती आर्थिक और अवसंरचनात्मक उपस्थिति ने क्षेत्रीय भू–राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा प्रदान की है। ग्वादर, हंबनटोटा तथा अन्य सामरिक परियोजनाएँ चीन की तथाकथित "मोतियों की माला" रणनीति को प्रतिबिंबित करती हैं, जिसके माध्यम से वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव विस्तार कर रहा है तथापि, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि चीन के उदय ने भारत की क्षेत्रीय भूमिका को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया है। भारत ने 'पड़ोस प्रथम' तथा 'सागर' जैसी नीतियों, सांस्कृतिक निकटता, विकास सहयोग और बहुआयामी कूटनीतिक पहलों के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को केवल आर्थिक परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि उसके सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और विकासात्मक आयामों के समेकित संदर्भ में समझना आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में दक्षिण एशिया की शक्ति–राजनीति और क्षेत्रीय व्यवस्था पर इन प्रक्रियाओं का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है।

मुख्य शब्द

नए सिल्क रोड, यूरेशियाई कनेक्टिविटी, आर्थिक गलियारा, सैटेलाइट स्टेट, बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI), *दक्षिण एशिया.*

परिचय

चीन के राष्ट्रपति शि जिनपिंग द्वारा वर्ष 2013 में प्रस्तुत बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) आज विश्व की सबसे व्यापक अंतर–महाद्वीपीय संपर्क परियोजनाओं में से एक बन चुकी है। इसकी परिकल्पना चीन के लिए वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग विकसित करने, समुद्री चोक–पॉइंट्स पर निर्भरता कम करने तथा अपने औद्योगिक अधिशेष के लिए नए बाजार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रारंभ में इसे 'वन बेल्ट, वन रोड' के नाम से प्रचारित किया गया, किंतु बाद में इसे अधिक समावेशी

स्वरूप देने के लिए 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' नाम प्रदान किया गया। चीन इसे आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने वाली विकासात्मक पहल के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका घोषित उद्देश्य यूरेशिया तथा अन्य क्षेत्रों को व्यापारिक और अवसंरचनात्मक नेटवर्क से जोड़ना है। हालाँकि, 2013 से 2026 तक की घटनाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि BRI केवल आर्थिक विकास की परियोजना नहीं है, बल्कि इसके भीतर व्यापक भू–राजनीतिक और भू–आर्थिक महत्वाकांक्षाएँ भी निहित हैं। विशेषकर दक्षिण एशिया में इसके प्रभावों का अध्ययन यह संकेत देता है कि यह पहल कई मामलों में क्षेत्रीय प्रभाव–विस्तार, आर्थिक निर्भरता निर्माण तथा रणनीतिक उपस्थिति सुदृढ़ करने के साधन के रूप में कार्य कर रही है।

दक्षिण एशिया ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रभाव–क्षेत्र का केंद्र रहा है, जिसकी आधारशिला उसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक क्षमता, सैन्य संरचना और हिंद महासागर में सामरिक उपस्थिति पर आधारित रही है किंतु क्षेत्र के अनेक देशों में भारत के प्रति 'बिग ब्रदर सिंड्रोम' की धारणा भी विद्यमान रही है। परिणामस्वरूप, जब चीन ने BRI का विस्तार दक्षिण एशिया में किया और भारत ने इसका विरोध किया, तब अधिकांश क्षेत्रीय देशों ने इसे भारत और चीन के बीच संतुलन स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा। भूटान को छोड़कर लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों ने चीन के साथ इस परियोजना से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जबकि पाकिस्तान का CPEC इस पूरी पहल का प्रमुख प्रतीक बनकर उभरा। समय के साथ BRI का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है। पारंपरिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के अतिरिक्त अब इसमें डिजिटल सिल्क रोड, हेल्थ सिल्क रोड तथा ग्रीन BRI जैसी अवधारणाएँ सम्मिलित हो चुकी हैं। पर्यावरणीय स्थिरता, हरित विकास और "स्मॉल एंड ब्यूटीफुल" परियोजनाओं पर बढ़ता जोर इस परिवर्तन का संकेत है साथ ही चीन एशिया से आगे बढ़कर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी अपने आर्थिक एवं रणनीतिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है। इस दृष्टि से BRI केवल एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि चीन की दीर्घकालिक वैश्विक शक्ति–परिकल्पना और उसके राष्ट्रीय पुनरुत्थान के व्यापक लक्ष्य का प्रमुख आधार बन चुकी है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) की प्रकृति और उसके व्यापक प्रभावों को समझने के लिए यथार्थवाद, नव–यथार्थवाद तथा भू–आर्थिकता की अवधारणाएँ अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति और सुरक्षा है, जहाँ प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा तथा प्रभाव–विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जॉन मियर्सहाइमर के आक्रामक यथार्थवाद को देखा जाए तो BRI केवल आर्थिक सहयोग की परियोजना नहीं, बल्कि चीन द्वारा अपने आर्थिक संसाधनों के माध्यम से रणनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय प्रभुत्व को सुदृढ़ करने का साधन प्रतीत होती है। उनके अनुसार महान शक्तियाँ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभाव–क्षेत्रों का विस्तार करती हैं, और BRI इसी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति है।

नव–यथार्थवादी विचारक केनेथ वाल्ट्ज के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्वभावतः अराजक होती है, जहाँ कोई सर्वोच्च सत्ता मौजूद नहीं होती। ऐसी स्थिति में राज्य शक्ति–संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाते हैं। दक्षिण एशिया में BRI के माध्यम से चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत को भी संतुलनकारी नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया है। क्वाड, इंडो–पैसिफिक रणनीति तथा क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएँ इसी प्रतिक्रिया के प्रमुख उदाहरण हैं। परिणामस्वरूप एक ऐसी सुरक्षा दुविधा उत्पन्न होती है, जिसमें चीन अपनी गतिविधियों को विकास और सहयोग का माध्यम बताता है, जबकि भारत उन्हें संभावित सामरिक घेराव के रूप में देखता है। भू–आर्थिक दृष्टिकोण से यह परिघटना और अधिक स्पष्ट होती है। एडवर्ड लुटवाक के अनुसार आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा का स्वरूप सैन्य संघर्ष से आगे बढ़कर आर्थिक साधनों पर आधारित हो गया है। चीन ने निवेश, व्यापार, संपर्क नेटवर्क और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक परस्पर निर्भरता को रणनीतिक प्रभाव के उपकरण में परिवर्तित किया है।

इस प्रकार वर्तमान दक्षिण एशिया वैश्विक शक्ति–प्रतिस्पर्धा का एक संवेदनशील भू–राजनीतिक क्षेत्र बन चुका है, जहाँ चीन की निवेश–आधारित कूटनीति, भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व की आकांक्षा तथा अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों की नई रणनीतिक पहलों के बीच निरंतर और जटिल अंतःक्रियाएँ विकसित हो रही हैं। BRI को समझने के लिए इन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का समन्वित अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।

वर्तमान मान आर्थिक स्थिति एवं रणनीतिक दिशा का विश्लेषण

वर्तमान वैश्विक भू–राजनीतिक परिवर्तनों तथा चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026–2030) के संदर्भ में बेल्ट एंड

रोड इनिशिएटिव (BRI) एक नए विकासात्मक चरण में प्रवेश कर चुकी है। प्रारंभिक वर्षों में यह पहल मुख्यतः सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और औद्योगिक गलियारों जैसे विशाल भौतिक अवसंरचनात्मक निवेशों पर आधारित थी, किंतु अब इसका स्वरूप अधिक परिष्कृत, जोखिम–संतुलित और "उच्च–गुणवत्ता विकास" केंद्रित बन गया है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि चीन की व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव–विस्तार रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नई रणनीतिक दिशा के अंतर्गत BRI को तकनीकी आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता से जोड़ा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अवसंरचना, डेटा नेटवर्क, स्वच्छ ऊर्जा तथा उन्नत विनिर्माण इसके प्रमुख क्षेत्र बन चुके हैं। परिणामस्वरूप, यह पहल अब केवल भौतिक संपर्क का माध्यम नहीं रही, बल्कि वैश्विक तकनीकी मानकों, डिजिटल शासन संरचनाओं और आर्थिक परस्पर निर्भरता को प्रभावित करने वाला एक व्यापक भू–आर्थिक उपकरण बन गई है। 150 से अधिक देशों की भागीदारी और एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ BRI विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय विकास पहलों में से एक है। BRI के वर्तमान चरण में पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा संक्रमण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व में ऋण–भार और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर हुई आलोचनाओं के बाद चीन ने "ग्रीन BRI" की अवधारणा को केंद्र में रखा है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि ऋण पुनर्गठन और वित्तीय सहायता के माध्यम से "ऋण–जाल कूटनीति" संबंधी आलोचनाओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

आर्थिक आयामों के साथ–साथ BRI का सामरिक महत्व भी निरंतर बढ़ा है, विशेषकर दक्षिण एशिया में। चीन ने निवेश और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव को विस्तार दिया है, जिससे कई देशों को नई साझेदारियों के विकल्प प्राप्त हुए हैं। इससे क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन और कूटनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया में विकसित चीनी बंदरगाह, निगरानी तंत्र और दोहरे उपयोग वाली अवसंरचनाएँ अब केवल आर्थिक परिसंपत्तियाँ नहीं रहीं, बल्कि व्यापक भू–राजनीतिक महत्व प्राप्त कर चुकी हैं। इस प्रकार 2026 का BRI आर्थिक विकास, तकनीकी नेतृत्व, पर्यावरणीय संक्रमण और सामरिक प्रभाव के समन्वित मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है।

भारत के पारंपरिक प्रभुत्व का क्षरण और भारत–विरोधी गतिविधियों के नए केंद्र

दक्षिण एशिया में भारत का पारंपरिक प्रभाव लंबे समय तक भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक संबंधों तथा आर्थिक परस्पर निर्भरता पर आधारित रहा। नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों की विदेश एवं सुरक्षा नीतियों में नई दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती थी किंतु चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के अंतर्गत हुए व्यापक निवेशों ने इन देशों को रणनीतिक विकल्प प्रदान किए, जिससे वे भारत–केंद्रित निर्भरता से बाहर निकलकर अधिक संतुलित और बहुआयामी विदेश नीति अपनाने लगे। चीन की 'ग्लोबल सिक्योरिटी इनीशिएटिव' (GSI) ने इस प्रक्रिया को और गति दी है। यह पहल केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, सुरक्षा और कानून–प्रवर्तन संस्थाओं के साथ गहरे सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय देशों को चीन की सुरक्षा संरचना से जोड़ने का प्रयास भी करती है। परिणामस्वरूप, चीन दक्षिण एशिया के अनेक देशों का प्रमुख व्यापारिक साझेदार होने के साथ–साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों का महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्तिकर्ता भी बन चुका है।

इस आर्थिक और सैन्य निकटता का प्रभाव क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जिन क्षेत्रों में चीनी परियोजनाएँ स्थापित हुई हैं, वहाँ चीन की सामरिक उपस्थिति लगातार बढ़ी है। इससे भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताएँ जटिल हुई हैं, क्योंकि कुछ देशों ने चीनी नौसैनिक पोतों, अनुसंधान जहाजों तथा निगरानी अवसंरचनाओं को अपने क्षेत्रों में संचालन की अनुमति दी है। इस प्रकार, BRI ने केवल आर्थिक परिदृश्य ही नहीं बदला, बल्कि दक्षिण एशिया की भू–राजनीतिक संरचना को भी नए रूप में परिवर्तित कर दिया है।

एशियाई देशों का समकालीन संक्षिप्त विश्लेषण

पाकिस्तान

चीन की दक्षिण एशियाई रणनीति में पाकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। CPEC के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह, ऊर्जा और परिवहन अवसंरचना में विशाल निवेश ने दोनों देशों के संबंधों को और गहरा किया है। गिलगित–बाल्टिस्तान से गुजरने वाला यह गलियारा भारत की संप्रभुता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है, जबकि बढ़ता सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन को प्रभावित कर रहा है।

बांग्लादेश

बांग्लादेश लंबे समय तक भारत का विश्वसनीय पड़ोसी रहा, किंतु हालिया राजनीतिक परिवर्तनों और चीनी निवेशों ने उसकी विदेश नीति को नई दिशा दी है। चीन समर्थित नौसैनिक अवसंरचना और रक्षा सहयोग ने बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक समीकरणों को बदला है। परिणामस्वरूप, भारत–बांग्लादेश संबंधों में नई चुनौतियाँ और अनिश्चितताएँ उभर रही हैं।

श्रीलंका

श्रीलंका चीन की आर्थिक और सामरिक सक्रियता का प्रमुख केंद्र बन चुका है। हंबनटोटा बंदरगाह से लेकर नए औद्योगिक निवेशों तक, बीजिंग की उपस्थिति लगातार सुदृढ़ हुई है। हिंद महासागर में चीनी अनुसंधान पोतों और नौसैनिक गतिविधियों की बढ़ती आवृत्ति भारत की सुरक्षा चिंताओं को गहरा करती है, जिससे कोलंबो संतुलनकारी कूटनीति अपनाने को विवश है।

नेपाल

नेपाल चीन और भारत के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी राष्ट्र है, जो अब संतुलित और स्वायत्त विदेश नीति की ओर अग्रसर दिखाई देता है। यद्यपि अनेक चीनी परियोजनाएँ अपेक्षित गति नहीं पकड़ सकीं, फिर भी आर्थिक निवेशों के माध्यम से बीजिंग का प्रभाव बढ़ा है। नेपाल स्वयं को 'बफर स्टेट' नहीं, बल्कि 'कनेक्टिविटी ब्रिज' के रूप में स्थापित करना चाहता है।

भूटान

भूटान परंपरागत रूप से भारत का घनिष्ठ सहयोगी रहा है, किंतु चीन के साथ बढ़ते सीमा–वार्तालापों ने नए भू–राजनीतिक प्रश्न खड़े किए हैं। डोकलाम क्षेत्र का सामरिक महत्व आज भी बना हुआ है। चीन की क्रमिक कूटनीतिक सक्रियता और सीमा क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विस्तार भारत के लिए सतर्कता और संतुलित रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

भारत की प्रतिक्रिया का समग्र विश्लेषण

दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता, विशेषकर उसकी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विस्तार ने भारत के समक्ष नई सामरिक चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। इन परिस्थितियों में भारत ने केवल प्रतिरोध की नीति अपनाने के बजाय एक व्यापक, संतुलित और बहुआयामी रणनीति विकसित की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन बनाए रखना तथा पड़ोसी देशों को सहयोग और विकास का वैकल्पिक मॉडल उपलब्ध कराना है। समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने 'कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव' को पुनर्जीवित कर उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय मंच के रूप में विकसित किया है। यह व्यवस्था आतंकवाद–रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी तथा समुद्री डकैती की रोकथाम जैसे विषयों पर हिंद महासागर के देशों को साझा सुरक्षा ढाँचे से जोड़ती है। इसके माध्यम से भारत क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के साथ–साथ चीन की बढ़ती सुरक्षा पहल के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) और ग्वादर बंदरगाह के सामरिक महत्व को देखते हुए भारत ने ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के विकास को प्राथमिकता दी है। यह परियोजना भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान करती है। यद्यपि क्षेत्रीय अस्थिरताओं ने इसकी उपयोगिता पर कुछ प्रश्न खड़े किए हैं, फिर भी इसका सामरिक महत्व बना हुआ है। इसी क्रम में ओमान के डुक्म बंदरगाह तक प्राप्त पहुँच ने पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता को और सुदृढ़ किया है। पूर्वी समुद्री क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के प्रत्युत्तर में भारत ने ग्रेट निकोबार परियोजना को तीव्र गति प्रदान की है। आधुनिक बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा सैन्य अवसंरचना से युक्त यह परियोजना बंगाल की खाड़ी और मलक्का जलडमरूमध्य के समीप भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करती है तथा समुद्री चुनौतियों का प्रभावी सामना करने की क्षमता प्रदान करती है।

इसी प्रकार, 'क्वाड' के माध्यम से भारत ने समुद्री निगरानी और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा दी है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की निगरानी, नौवहन सुरक्षा और समुद्री पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली पहलें क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे अवैध एवं संदिग्ध समुद्री गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी संभव हो पाई है। वैश्विक स्तर पर भी भारत ने बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से वह विकासशील देशों के हितों, आर्थिक सहयोग तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संतुलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यह भारत की व्यावहारिक कूटनीति का प्रतीक है, जिसमें वह प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है।

अंततः स्पष्ट है कि चीन की बढ़ती क्षेत्रीय सक्रियता के उत्तर में भारत ने सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और समुद्री स्तर पर एक समन्वित एवं दूरदर्शी रणनीति विकसित की है। यह केवल प्रतिरोध की नीति नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, सहयोग और दीर्घकालिक सामरिक संतुलन की स्थापना का व्यापक प्रयास है, जो बदलते दक्षिण एशियाई भू–राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाता है।

निष्कर्ष

चीन की बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (BRI) ने पिछले एक दशक में दक्षिण एशिया के भू–राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा परिवेश को गहराई से प्रभावित किया है। प्रारम्भ में इसे अवसंरचना निर्माण और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की विकासात्मक परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु समय के साथ इसके सामरिक और भू–राजनीतिक आयाम अधिक स्पष्ट होकर सामने आए हैं। 2025–26 के घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि BRI केवल आर्थिक निवेश का माध्यम नहीं, बल्कि चीन की व्यापक वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है, जिसके माध्यम से वह अपने राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों का विस्तार कर रहा है।

दक्षिण एशिया में पाकिस्तान का चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह, बांग्लादेश में समुद्री अवसंरचना का विकास, मालदीव के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग, म्यांमार के सामरिक द्वीपों पर तकनीकी विस्तार तथा भूटान से जुड़े सीमा क्षेत्रों में चीन की सक्रियता ये सभी घटनाएँ मिलकर क्षेत्र में उसके दीर्घकालिक प्रभाव निर्माण की रणनीति को प्रतिबिंबित करती हैं। इन परियोजनाओं ने चीन को केवल आर्थिक उपस्थिति ही नहीं दी है, बल्कि उसे समुद्री मार्गों, व्यापारिक संपर्कों और सामरिक बिंदुओं पर भी महत्वपूर्ण पहुँच प्रदान की है परिणामस्वरूप, दक्षिण एशिया का शक्ति–संतुलन अधिक जटिल और प्रतिस्पर्धी बन गया है।

भारत के लिए यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता के आधार पर निर्मित उसका पारंपरिक क्षेत्रीय प्रभाव अब नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में केवल भावनात्मक या ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित कूटनीति पर्याप्त नहीं रह गई है। आवश्यकता एक ऐसे बहुआयामी दृष्टिकोण की है जो आर्थिक सहयोग, संपर्क अवसंरचना, सुरक्षा साझेदारी और विकासात्मक सहायता को समान महत्व दे। इसी उद्देश्य से भारत ने 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को अधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करते हुए क्षेत्रीय सहयोग और सामरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के प्रयास किए हैं। इस दिशा में चाबहार बंदरगाह, ग्रेट निकोबार परियोजना, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव तथा क्वाड (QUAD) जैसी पहलों ने भारत की सामरिक क्षमता और समुद्री सुरक्षा दृष्टि को नई मजबूती प्रदान की है।

अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग भी इस बात का संकेत है कि भारत क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन को बनाए रखने और मुक्त, सुरक्षित तथा नियम–आधारित समुद्री व्यवस्था के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहा है साथ ही, भारत ने संप्रभुता संबंधी चिंताओं के कारण BRI को औपचारिक समर्थन देने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है और इसके विकल्प के रूप में अधिक पारदर्शी तथा सहभागी विकास मॉडल को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान परिस्थितियों में दक्षिण एशिया एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है जहाँ कोई एक शक्ति निर्णायक प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। क्षेत्रीय राष्ट्र आर्थिक विकास, अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि वे विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ समानांतर संबंध विकसित कर रहे हैं।

अंततः, दक्षिण एशिया की उभरती हुई वास्तविकता एक बहुध्रुवीय भू–आर्थिक व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इस व्यवस्था में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री हितों और क्षेत्रीय प्रभाव का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने पड़ोसी देशों को कितनी प्रभावशीलता से ऐसे विकल्प उपलब्ध करा पाता है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य, राजनीतिक रूप से विश्वसनीय और संप्रभुता का सम्मान करने वाले हों। वस्तुतः, BRI और उसके प्रति भारत की प्रतिक्रिया केवल दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के दक्षिण एशिया में शक्ति, विकास, संपर्क और संप्रभुता के नए समीकरणों को समझने की कुंजी भी है।

सन्दर्भ सूची

1. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल (मार्च 2026) *चीन के राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026–2030) की रूपरेखा.* फॉरेन लैंग्वेजेज प्रेस, बीजिंग, अध्याय 23, पृ. 12–19।

2. वांग, क्रिस्टोफ नेडोपिल. (जुलाई 2025) *चाइना बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिवइन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025. ग्रीन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर,* फुडान यूनिवर्सिटी, यांगपु, शंघाई, पृ. 3–9।

3. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (15 मार्च 2026) *नेविगेटिंग द बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिवः व्हाई होस्ट–कंट्री एजेंसी इज द की टू सक्सेस.* आईआईएसडी, पब्लिकेशन्स, जेनेवा, पृ. 6–11।

4. अहमद, एस. एवं महमूद, ज़ेड. (जनवरी 2026) सीपीईसी द्वितीय चरण और पाकिस्तान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक परिवर्तन. *जर्नल ऑफ साउथ एशियन इकॉनॉमिक्स,* 12(3), 45–58।

5. अमीरी, एच. एवं खान, टी. (10 मार्च 2026) तालिबान की आर्थिक जीवनरेखाः अफगानिस्तान में चीनी खनन समझौतों की 2026 की प्रगति. *एशियन जियोपॉलिटिकल रिव्यू,* संस्करण 4, पृ. 89–95.।

6. भट्टराई, पी. (फरवरी 2026) हिमालयी बाधाएंः नव–यथार्थवादी युग में ट्रांस–हिमालयन नेटवर्क का पुनर्गठन. *काठमांडू पॉलिसी पेपर्स,* अंक 18, पृ. 14–22।

7. रहमान, एम. एवं चौधरी, ए. (अप्रैल 2026) बुनियादी ढांचे से डिजिटल सिल्क रोड तकः बीआरआई के तहत बांग्लादेश का हरित संक्रमण. *साउथ एशियन जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,* 9(1), 28–39।

8. सिंह, ए. के. एवं कपूर, आर. (2026) *हिंद महासागर में भारत की व्यापक रणनीतिः सागर और क्वाड के माध्यम से बीआरआई का मुकाबला.* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया, नई दिल्ली, अध्याय 4, पृ. 112–120।

––==00==––